# नवल टाइम्स

RNI No. UTTHIN/2012/42590

भारत सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

वर्ष : 14 अंकः 20 हिन्दी साप्ताहिक हरिद्वार, बृहस्पतिवार 05 जून 2025 मूल्यः 1 रूपया पृष्ठः 4


# राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

## कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर

**देहरादून( नवल टाइम्स )।** मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं, ई-वाहन टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं और पेंशन जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया। विक्रम व अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ होगा, केवल जीएसटी देय रहेगा। उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों की परीक्षा अब एक साथ आयोजित की जाएगी।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि सब-इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा भी एकसमान तरीके से कराई जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए। मानवाधिकार आयोग में 12 नए पद स्वीकृत किए गए। राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देशों पर बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अन्तर्गत पुनर्निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। उक्त के क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम में एराईवल प्लाजा पर प्रधानमंत्री भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अति विशिष्ट प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया जाना है। उक्त कार्य में अति विशिष्ट प्रकार की कलाकृति बनाये जाने की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गयी है।

उत्तराखण्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में विभागाध्यक्ष घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अधिसूचना 27.12.2024 के द्वारा गृह विभाग के सीधे नियन्त्रण में लाये जाने के फलस्वरूप विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग का आय-व्ययक सम्बन्धी समस्त कार्य प्रभावित होने के दृष्टिगत निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला को शासकीय अभिलेखों में विभागाध्यक्ष घोषित किये जाने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) वर्ष 2018 के अध्याय-1 में विभागाध्यक्षों की सूची सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग का गठन वर्ष, 2011 में किया गया है, तत्समय आयोग के संरचनात्मक ढांचे में कुल-47 पद सृजित किये गये थे। आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे का विगत 11 वर्षों में कार्य आवश्यकता के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया जा सका है, जिससे आयोग के दैनिक कार्य प्रभावित होने के कारण वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप आयोग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु पूर्व से सृजित ढांचे में 12 नवीन पदों को सृजित करते हुये उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग के वर्तमान संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्यांतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कार्मियों की पूर्व सेवाओं को उपादान की देयता हेतु जोडे जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है।

राज्य सरकार के साधनों का समुचित एवं विवकेपूर्ण उपयोग किये जाने तथा अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सुविधाजनक स्थिति प्रदान किये जाने के लिए सम्बन्धित विभागों एवं चयन संस्था/

आयोग के साथ विचारोपरान्त वर्दीधारी पदों (सिपाही एवं उप निरीक्षक) पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 एवं उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 के प्रख्यापन किये जाने का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। वन टाइम सेटेलमेंट के तहत विनियमित हुए पर्यावरण मित्रों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली, 1974 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु कैबिनेट द्वारा अनुमोदन दिया गया। शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में विनियमितीकरण नियमावली, 2013 के अन्तर्गत 859 पर्यावरण मित्रों को वन टाईम सेटलमेंट के तहत विनियमित किया गया था। उक्त विनियमितीकरण विषयक शासनादेश संख्या-1282, दिनांक 22.11.2016 में प्राविधानित था कि एक बार के लिए विनियमित किये जाने वाले उक्त कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अथवा अन्य किसी दशा में उक्त पद रिक्त होने पर स्वत: आउटसोर्स में परिवर्तित हो जायेंगे। उक्त प्राविधान के कारण सम्बन्धित कार्मिकों के आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्तानुसार वन टाइम सेटेलमेंट के तहत विनियमित हुए पर्यावरण मित्रों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली, 1974 का लाभ प्रदान किये जाने हेतु विनियमितीकरण विषयक शासनादेश संख्या-1282, दिनांक 22.11.2016 में संशोधन किये जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।

परिवहन विभागान्तर्गत उत्तराखण्ड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024 के प्रस्तर-09 के बिन्दु (2) में यह व्यवस्था थी कि नीति के तहत दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों के लिए धन विभिन्न अनुमन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा और एक गैर व्यपगत फंड के रूप में उत्तराखण्ड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड के नाम से एक एस्क्रो खाते में जमा किया जायेगा। बैंको द्वारा उक्त एस्क्रो खातों को खोलने हेतु कतिपय समस्यायें इंगित की गई है। इसके अतिरिक्त शासन के वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 जुलाई, 2023 के अनुसार बजटीय अनुदानों हेतु एस0एन0ए0 खाता खोलकर उसे आई0एफ0एम0एस0 से इंटीग्रेटड किया जाना अनिवार्य है। अत: एस्क्रो खाते के स्थान पर उत्तराखण्ड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन फंड के नाम से एस0एन0ए0 खाता खोले जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 02 जनवरी, 2019 में विद्युत बैटरी अथवा सोलर पॉवर अथवा सी0एन0जी0 से चलित यानों पर एक बारीय कर की दरें निर्धारित हैं। उक्त अधिसूचना में केन्द्रीय मोटरयान (नवां संशोधन) नियम, 2023 के नये नियम 125 ''एम'' के अन्तर्गत केवल प्लग इन हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान एवं स्ट्रांग हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान को भी देय मोटरयान कर से छूट दिए जाने का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय का उददेश्य वाहन स्वामियों को उक्त श्रेणी के वाहन क्रय एवं उसके उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना एवं प्रदूषण में कमी लाना भी है। उक्त कर छूट वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल एक बार के लिये ही वैध होगी। उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह-ग के पदों पर चयन किये जाने हेतु अधिसूचना दिनांक 17-08-2014 के द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, तदोपरान्त उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ढांचा शासनादेश सं0 441 दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के द्वारा 64 अस्थायी पदों का सृजन किया गया। जिसमें 02 पद डाइंग कैडर होने के दृष्टिगत वर्तमान में 62 पद ही सृजित है। वर्तमान में विभिन्न विभागों में कार्मिकों के भर्तियों के अधियाचनों की अधिकता के दृष्टिगत आयोग के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु आयोग के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संरचनात्मक ढ़ाचे में पूर्व सृजित 62 पदों के अतिरिक्त उप सचिव का 01 नियमित पद तथा विधि अधिकारी 01 पद, संविदा/आउटसोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 02 पद आउटसोर्स, कम्प्यूटर प्रोग्रामर का 01 पद आउटसोर्स, स्वागती का 01 पद आउटसोर्स, वाहन चालक के 03 पद आउटसोर्स तथा सुरक्षा कार्य हेतु 06 सुरक्षा कर्मियों आउटसोर्स के माध्यम से, इस प्रकार कुल 15 (01 नियमित पद तथा 14 आउटसोर्स के) नवीन पदों के सृजन का कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है।

# हरिद्वार के नए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संभाला चार्ज

## गिनाई प्राथमिकताएं, अधिकारियों को भी चेताया

**हरिद्वार( नवल टाइम्स )।** आईएएस अधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को हरिद्वार जिलाधिकारी के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। चार्ज संभालने के बाद जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जहां गुड गवर्नेंस को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया तो चेतावनी देते हुए कहा कि सही से काम नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मचारी एक्शन के लिए तैयार रहे।हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि आगामी मानसून सीजन और कांवड़ मेला उनकी प्रथमिकता है। कांवड़ मेला सकुशल सम्पन्न कराना है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ किया है कि वो कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सहारा जाएगा। लापरवाही करने वाले अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की सभी योजनाओं को आम जनता पहुंचने का कार्य किया जाएगा और समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के साथ ही आमजन से फीडबैक भी लिया जाएगा। यदि किसी अधिकारियों की

लापरवाही या कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि फिलहाल मानसून सीजन उनकी प्राथमिकता है। नगर निगम ने मानसून को लेकर क्या तैयारियां की है, उसको लेकर बैठक की जाएगी। यदि किसी कार्य की आवश्यकता है तो उसे भी जल्द पूरा कराया जाएगा। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि कावड़ मेले को लेकर उनके पास कम समय है। ऐसे में कांवड़ में लेकर तैयारियां तय समय पर करनी होगी।

## उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किया महाविद्यालयों का निरीक्षण

**हरिद्वार( नवल टाइम्स )।** संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा प्रो.ए.एस. उनियाल, उपनिदेशक डा.ममता डंयोडी नैथानी एवं सहायक निदेशक डा.प्रमोद डोबरियाल ने श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाओं, विश्वविद्यालय के मूल्यांकन केन्द्र व संग्रहण केन्द्र के सम्बन्ध में विभिन्न महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने महाविद्यालयों के स्ट्रांग रूम, मुख्य परीक्षा नियंत्रण कक्ष व परीक्षा कक्षों का निरीक्षण किया। एसएमजेएन कालेज में निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक प्रो.ए.एस.उनियाल ने कहा कि महाविद्यालय प्रबन्धन द्वारा कालेज में छात्र-छात्राओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं उपलब्ध हैं। उन्होंने महाविद्यालय में लागू किये गये ड्रेस कोड की सराहना करते हुए कहा कि महाविद्यालय परिसर, अध्यापन व परीक्षा कक्षों में लगाये गये सीसीटीवी कैमरे इसका प्रमाण हैं कि महाविद्यालय में समस्त परीक्षा शुचिता के साथ सम्पन्न करायी जा रही हैं। उपनिदेशक डा.ममता डंयोडी ने कहा कि उचित व्यवस्थाओं के चलते ही विश्वविद्यालय द्वारा एसएमजेएन कालेज को निरन्तर मूल्यांकन केन्द्र व संग्रहण केन्द्र बनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य परीक्षा प्रभारी डा.मनमोहन गुप्ता, सह परीक्षा प्रभारी प्रो.जगदीश चन्द्र आर्य, डा.संजय कुमार माहेश्वरी, डा.नलिनी जैन, विनय थपलियाल, डा.सुषमा नयाल, चिकित्सक डा.प्रदीप त्यागी आदि उपस्थित रहे। इससे पश्चात निरीक्षण दल ने राजकीय कॉलेज भूपतवाला, चमनलाल महाविद्यालय लण्ढौरा व राजकीय पीजी कालेज लक्सर का भी निरीक्षण किया तथा आवश्यक सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं को दुरुस्त पाया। इस दौरान उन्होंने सभी प्राचार्यों, प्राध्यापकों एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।

## सम्पादकीय

### राजनीति के लिए अनेक मुद्दे हैं!

पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो जनता से लेकर विपक्ष तक सब सरकार के साथ खड़े दिखाई दिये और अब जब पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है, जो कि कतई भी देशहित में नहीं है। राजनीति के अनेक मुद्दे हैं उन पर राजनीति करनी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बीच में सीजफायर की पृष्ठभूमि में देश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखा पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने मंगलवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की एक काल्पनिक बातचीत को दर्शाता पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में ट्रम्प मोदी से सरेंडर करने को कहते दिखाए गए हैं और जवाब में मोदी जी हजूर कहते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष करते हुए लिखा है- नरेंदर सरेंडर नहीं होना था। इस पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने पलटवार करते हुए एक बार फिर राहुल-मुनीर के पोस्टर को सोशल मीडिया पर जारी किया है। इस पोस्टर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल ने देर रात 11 बजे सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ दिखाया गया है। पोस्टर में मुनीर राहुल को निशान-ए-पाकिस्तान का प्रतीक चिन्ह पहना रहे हैं। इस पोस्टर के साथ ही लिखा गया है, कि वन एजेंडा, वन ड्रीम, जिसका उद्देश्य राहुल गांधी और पाकिस्तान के बीच कथित वैचारिक समानता दिखाना है। इससे पहले 20 मई को भी भाजपा नेता अमित मालवीय ने इसी तरह का एक पोस्टर साझा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। यह पोस्टर वॉर ऐसे वक्त में सामने आया जबकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश-विदेश में चर्चा जारी है। यहां विपक्ष जहां ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हो रही राजनीति और मोदी सरकार की विदेशी नीति को लेकर केंद्र पर निशाना साध रहा है, वहीं सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रवाद और सुरक्षा नीति के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना करने में लगी हुई है।

## बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया की जटिल पर्यावरण समस्या

बढ़ते तापमान, बदलते जलवायु एवं ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल कर समुद्र का जलस्तर तीव्रगति से बढ़ा रहे हैं। जिससे समुद्र किनारे बसे अनेक नगरों एवं महानगरों के डूबने का खतरा मंडराने लगा है। इंसानों को प्रकृति, पृथ्वी एवं पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो पर्यावरण, प्रकृति एवं पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोज्य यह दिवस दुनिया भर के लाखों लोगों को हमारे ग्रह की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के साझा मिशन के साथ एकजुट करता है। बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया की एक गंभीर एवं जटिल समस्या है, इसीलिये 2025 में इस दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित है। कोरिया गणराज्य वैश्विक समारोह की मेज़बानी करेगा। दशकों से प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया के हर कोने में फैल चुका है, यह हमारे पीने के पानी, हमारे खाने, हमारे शरीर, हमारे पर्यावरण में समा रहा है। इस प्लास्टिक कचरे की गंभीर समस्या से निपटने का एक वैश्विक संकल्प निश्चित ही एक समाधान की दिशा बनेगा। हर साल 430 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग दो-तिहाई केवल एक बार उपयोग के लिए होता है और जल्दी ही फेंक दिया जाता है।

1973 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के नेतृत्व में पर्यावरण जागरूकता के लिए यह दिवस सबसे बड़ा वैश्विक अभियान बन गया है, जो आज की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए 150 से अधिक देशों के विशाल वैश्विक दर्शकों को शामिल करता है। गत वर्ष इस दिवस की मेजबानी करते हुए सऊदी अरब ने भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए सकारात्मक प्रयासों का जश्न मनाया और पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाले निजी और परोपकारी संगठनों के लिए अधिक समर्थन और वित्त पोषण की घोषणा की। यह सर्वविदित है कि इंसान व प्रकृति के बीच गहरा संबंध है। इंसान के लोभ, सुविधावाद एवं तथाकथित विकास की अवधारणा ने पर्यावरण का भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण न केवल नदियां, वन, रेगिस्तान, जलस्रोत सिकुड़ रहे हैं बल्कि ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तापमान का 50 डिग्री पार करना जो विनाश का संकेत तो है ही, जिनसे मानव जीवन भी असुरक्षित होता जा रहा है। इन वर्षों में बढ़ी हुई गर्मी एवं तापमान ने न केवल जीवन को जटिल बनाया बल्कि अनेक लोगों की जान भी गयी। पूरी दुनिया में बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु अराजकता और जैव विविधता विनाश का एक जहरीला मिश्रण स्वस्थ भूमि को रेगिस्तान में बदल रहा है, संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र को मृत क्षेत्रों में बदल रहा है और मानव जीवन पर तरह-तरह के खतरे पैदा कर रहा है। प्रकृति को पस्त करने, वायु एवं जल प्रदूषण, कृषि फसलों पर घातक प्रभाव, मानव जीवन एवं जीव-जन्तुओं के लिये जानलेवा साबित होने के कारण समूची दुनिया में बढ़ते प्लास्टिक एवं माइक्रोप्लास्टिक के कण एक बड़ी चुनौती एवं संकट है। पिछले दिनों एक अध्ययन में मनुष्य के मस्तिष्क में प्लास्टिक के नैनो कणों के पहुंचने पर चिंता जतायी गई थी। दावा था कि प्रतिदिन सैकड़ों माइक्रोप्लास्टिक कण सांसों के जरिये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे तमाम नये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय शोध-सर्वेक्षण-अध्ययन चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी सांसों, प्रकृति, पर्यावरण, पेयजल व फसलों में घातक माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी एक गंभीर संकट है।

# भारत का पर्यावरण परिवर्तन

भारत में हमेशा से प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान रहा है। जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है, पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। यह विश्वास सदियों से हमारी जीवनशैली का हिस्सा रहा है। पिछले 11 वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इस प्राचीन ज्ञान को मजबूत और व्यावहारिक कार्रवाई में बदल दिया गया है। भारत वैश्विक जलवायु प्रयासों में अनुयायी से आगे बढ़कर एक नेता बन गया है। स्पष्ट नीतियों, सार्वजनिक भागीदारी और स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता के लिए एक मजबूत प्रयास के माध्यम से, सरकार सभी के लिए एक हरित, स्वस्थ और अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए काम कर रही है।

**विश्व मंच पर जलवायु चैंपियन**

भारत को वर्ष 2014 के वैश्विक जलवायु वार्ता में एक संकोची भागीदार के रूप में देखा गया था। सरकार के जलवायु न्याय और समानता की अवधारणाएँ लाते ही यह बदल गया। जिसने वैश्विक जलवायु कथा को नया रूप दिया। पेरिस में सीओपी 21 (21 पार्टियों का सम्मेलन) में, भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्त्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने का संकल्प लिया; नवंबर 2021 में समय से पहले यह लक्ष्य पूरा हुआ। ग्लासगो में सीओपी 26 में, पीएम मोदी ने लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) लॉन्च किया, जिसमें टिकाऊ आदतों को प्रोत्साहित किया गया और बेकार उपयोग की तुलना में विचारशील उपभोग को बढ़ावा दिया गया। भारत ने जलवायु कार्रवाई के लिए पाँच प्रमुख लक्ष्य, पंचामृत भी पेश किया। बाकू में सीओपी 29 (नवंबर 2024) में, भारत ने वैश्विक भागीदारी के माध्यम से जलवायु अनुकूलन और स्वच्छ ऊर्जा में अपनी प्रगति का प्रदर्शन किया। स्वीडन, सीडीआरआई (आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन), आईएसए (अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन) और एनआरडीसी (प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद) के सहयोग से आपदा रोधी अवसंरचना, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन, सौर ऊर्जा और महिलाओं के नेतृत्व वाली जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित सत्र आयोजित किए गए।

**अक्षय ऊजा: वादों से लेकर प्रदर्शन तक**

भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, और अब तक की सबसे अधिक वार्षिक क्षमता वृद्धि हासिल की है। यह प्रगति स्वच्छ, हरित भविष्य के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में, भारत ने अक्षय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट की वृद्धि की, जिससे कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 220.10 गीगावाट हो गई, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 198.75 गीगावाट थी। यह 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य की दिशा में मजबूत प्रगति को दर्शाता है। भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में 25.46 गुना वृद्धि देखी गई, जो 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर अप्रैल 2025 में 71.78 गीगावाट हो गई। सौर टैरिफ में 65% की गिरावट आई, जो 2014-15 में 6.17रुपये /किलो वाट से घटकर 2024-25 में 2.15रुपये /किलो वाट, दुनिया में सबसे कम हो गई। पवन ऊर्जा क्षमता में 2.38 गुना वृद्धि हुई है, जो मार्च 2014 में 21.04 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में 50.04 गीगावाट हो गई है। सरकार ने 2030 तक 140 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा क्षमता में 2014 से 84% की वृद्धि देखी गई है, जो 2025 में 4.78 गीगावाट से बढ़कर 8.78 गीगावाट हो गई है। सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारत अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में 7वें स्थान पर है।

**राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन**

जनवरी 2023 में लॉन्च किए गए इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 एमएमटी वार्षिक क्षमता हासिल करना है, जिसमें 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश, 6 लाख नौकरियों का सृजन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना शामिल है।

**पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना ( पीएमएसजीएमबीवाई )**

15 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएमएसजीएमबीवाई दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल है। कम आय वाले परिवारों को लाभ पहुँचाने पर केंद्रित इस योजना ने अप्रैल 2025 तक 11.88 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पहुँचा दिया है। एक समर्पित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सब्सिडी और ऋण तक आसान पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना अधिक सुलभ और कुशल हो जाता है।

**आदर्श सौर ग्राम 7 प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक प्रमुख घटक**

इस प्रमुख घटक के तहत, विकेंद्रीकृत सौर अपनाने और ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक सौर ऊर्जा संचालित मॉडल गांव विकसित किया जाएगा। 800 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ, प्रत्येक चयनित गांव को केंद्रीय वित्तीय सहायता में 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। पात्र गाँव 5,000 (या विशेष श्रेणी के राज्यों में 2,000) से अधिक आबादी वाले राजस्व गाँव होने चाहिए। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में सौर ऊर्जा संचालित ग्रामीण विकास के अनुकरणीय मॉडल बनाना है।

**पीएम-कुसुम ( प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान ) योजना**

मार्च 2019 में शुरू की गई, पीएम-कुसुम योजना सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई प्रणालियों का समर्थन करके कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देती है। यह नए सौर पंपों और मौजूदा पंपों को सौर ऊर्जा से भरने के लिए 30% से 50% केंद्रीय सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का लक्ष्य आने वाले वर्षों में 49 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है, जिससे किसानों को विश्वसनीय ऊर्जा मिल सके और कार्बन उत्सर्जन में कमी आए।

**उजाला योजना ( सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति )**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई, उजाला (सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति) एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट और पंखे वितरित करके ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है। शुरू में डीईएलपी (घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम) नाम से जानी जाने वाली इस योजना ने बिजली की खपत को कम करने और लाखों लोगों के लिए टिकाऊ प्रकाश व्यवस्था को किफायती बनाने में मदद की है। 6 जनवरी 2025 तक, उजाला योजना ने 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए हैं।

**संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा: प्रकृति पलटवार करती है**

पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए योजनाओं से ज़्यादा की ज़रूरत होती है, इसके लिए मज़बूत फंडिंग, प्रभावी क्रियान्वयन और सामुदायिक भागीदारी की ज़रूरत होती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाले देशों में से एक भारत, संरक्षण का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण बजटीय कदम उठा रहा है।

**जैव विविधता समृद्धि:** हालाँकि पृथ्वी की भूमि का सिर्फ़ 2.4% हिस्सा भारत में है, लेकिन यहाँ वैश्विक प्रजातियों का 7-8% हिस्सा पाया जाता है, जिसमें 45,000 से ज़्यादा पौधे और 91,000 से ज़्यादा जानवर शामिल हैं।

**जैव विविधता हॉटस्पॉट:** भारत में 4 प्रमुख वैश्विक हॉटस्पॉट शामिल हैं; हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर और निकोबार द्वीप समूह। भारत की पर्यावरणीय सफलता ऊर्जा से परे भी फैली हुई है

**वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है**

दिसंबर 2024 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023, रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत का वन क्षेत्र 2013 में 698,712 वर्ग किमी से बढ़कर 2023 में 715,343 वर्ग किमी हो गया है। देश का कार्बन सिंक 30.43 बिलियन टन ष्टह्र2 समतुल्य तक पहुँच गया है, जो 2005 से 2.29 बिलियन टन बढ़ा है। यह प्रगति भारत के एनडीसी(राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) लक्ष्य 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन के अनुरूप है, जो वन संरक्षण और आग की घटनाओं में कमी को दर्शाता है।

**बाघों की आबादी दोगुनी से भी ज़्यादा हुई**

अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 (आमतौर पर चार साल के चक्रों में किया जाता है) के 5वें चक्र के सारांश रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कम से कम 3682 बाघ हैं और अब यहाँ दुनिया की जंगली बाघ आबादी का 75% से ज़्यादा हिस्सा रहता है।

**कुछ प्रमुख उपलब्धियां**

13 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

जम्मू-कश्मीर में पल्ली भारत की पहली कार्बन-न्यूट्रल पंचायत बन गई।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं।

देश में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है

नमामि गंगे मिशन: एक पवित्र परिवर्तन

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)]

गोबरधन (गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन)

अब तक आपदा तैयारी के लिए 46,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

16 एनडीआरएफ बटालियनों का गठन, बुनियादी ढांचे को उन्नत किया गया है।

डायल 112 आपातकालीन प्रणाली की तैनाती।

विरासत, पर्यटन और स्थिरता

पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ बुनियादी ढांचे का विकास शासन की नई पहचान है। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे जैसी परियोजनाएं प्रगति और संरक्षण के इस संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।

केदारनाथ रोपवे परियोजना: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मोड पर विकसित किया जा रहा है। रोपवे परियोजना केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक वरदान होगी क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक और तेज़ कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और एक दिशा में यात्रा का समय लगभग 8 से 9 घंटे से घटाकर लगभग 36 मिनट कर देगी।

हेमकुंड साहिब रोपवे: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम - पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में दो प्रमुख रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से एक हेमकुंड साहिब जी से जुड़ती है, जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जहां सालाना 1.5-2 लाख तीर्थयात्री आते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, फूलों की घाटी के निकट स्थित यह परियोजना पर्यावरण अनुकूल परिवहन के माध्यम से नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए सुगम पहुंच सुनिश्चित करेगी।

जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सटीक ही कहा, हमारा ग्रह एक है, लेकिन हमारे प्रयास अनेक होने चाहिए। भारत की 11 साल की यात्रा यह साबित करती है कि सतत विकास कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक जीवंत, प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है। गंगा की गहरी सफाई से लेकर वैश्विक अक्षय ऊर्जा दिग्गज बनने तक, और चीतों को पुनर्जीवित करने से लेकर सौर ऊर्जा से गांवों को ऊर्जा देने तक, भारत एक नई पारिस्थितिक कथा लिख रहा है जो विरासत को नवाचार, स्थानीय कार्रवाई को वैश्विक नेतृत्व और दूरदर्शिता को अथक निष्पादन के साथ जोड़ती है। भारत का हरित परिवर्तन केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं है। यह लोगों का आंदोलन है, एक वैश्विक प्रतिबद्धता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वादा है।

# पीएसपी से 250 मेगावाट का वाणिज्यिक सफल उत्पाद शुरू

## केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने की टीएचडीसी द्वारा भारत के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट, टिहरी पीएसपी की पहली इकाई के सीओडी प्रक्रिया की शुरुआत की सराहना

**ऋषिकेश( नवल टाइम्स )।** टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड टीएचडीसीआईएल विद्युत क्षेत्र के अग्रणी पीएसयू ने उत्तराखंड के टिहरी में 1000 मेगावाट के वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट पीएसपी की पहली इकाई 250 मेगावाट की सीओडी प्रक्रिया की सफल शुरुआत करने की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा में विशिष्ट सफलता के रूप में दर्ज हुई है, जिसने टिहरी पीएसपी को किसी भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई द्वारा निर्मित सबसे बड़ा पंप स्टोरेज प्लांट और देश में पहला वेरिएबल स्पीड पीएसपी के रूप में स्थापित किया है कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, मनोहर लाल ने वर्चुअल मोड के माध्यम से टिहरी पीएसपी की प्रथम यूनिट के प्रचालन का आधिकारिक उद्घाटन किया।

इस अवसर पर पंकज अग्रवाल आईएएस सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार आकाश त्रिपाठी आईएएस अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार गुरदीप सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी आर.के.विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसीआईएल शैलेन्द्र सिंह, निदेशक कार्मिक टीएचडीसीआईएल भूपेन्द्र गुप्ता, निदेशक तकनीकी, टीएचडीसीआईएल एवं श्री सिपन कुमार गर्ग, निदेशक वित्त टीएचडीसीआईएल भी उपस्थित रहे मनोहर लाल केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, भारत सरकार ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि टिहरी में भारत के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट की प्रथम यूनिट का सफल प्रचालन केवल टीएचडीसीआईएल की एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक साहसिक कदम है।

वेरिएबल स्पीड प्रौद्योगिकी हमें सटीकता के साथ विद्युत प्रवाह का प्रबंधन करने की अनुमति देती है, जिससे हमारा ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र अधिक स्मार्ट और अधिक लचीला बनता है मंत्री ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की पूरी टीम, कार्यान्वयन के अन्य भागीदारों तथा प्रत्येक व्यक्ति को बधाई दी जिन्होंने इस ऐतिहासिक सफलता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया विद्युत मंत्रालय के सचिव, पंकज अग्रवाल ने कमीशनिंग की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि टिहरी में वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट एक अग्रणी विकास है, जो हमारे ग्रिड के लचीलेपन को सुदृढ़ बनाता है। यह अक्षय ऊर्जा की बढ़ती मात्रा को एकीकृत करने और स्वच्छ, विश्वसनीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र की ओर ट्रांसमिशन के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री गुरदीप सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि जलविद्युत क्षेत्र में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की उच्च स्तरीय अभियांत्रिकी क्षमताओं को दर्शाती है। पीएसपी की यह उपलब्धि देश भर में भविष्य में निर्मित होने वाले पीएसपी के विकास के लिए एक विशेष मिसाल कायम करेगी। टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आर.के. विश्नोई ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर टिहरी पीएसपी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी और कहा कि एक बार पूरी तरह कमीशन हो जाने पर यह परियोजना टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स की क्षमता को 2400 मेगावाट तक बढ़ा देगी, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यह परियोजना ऑफ-पीक अधिशेष ऊर्जा को पीकिंग पावर में परिवर्तित करने, ग्रिड लचीलापन बढ़ाने और चौबीस घंटे विद्युत उपलब्ध कराने में सहयोग देने में सहायक होगी लचीली पीकिंग पावर और महत्वपूर्ण ग्रिड संतुलन समर्थन प्रदान करने के लिए परिकल्पित की गई टिहरी वेरिएबल स्पीड पीएसपी वैश्विक मंच पर भारत की आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा का प्रबंधन करने की क्षमता में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप प्रतिनिधित्व करती है। 250 मेगावाट की वेरिएबल स्पीड वाली पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर यूनिट, और इसके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंट्रोल सिस्टम जीई वर्नोवा द्वारा आपूर्ति किए गए हैं। जीई वर्नोवा एक वैश्विक ऊर्जा कंपनी है जो हाइड्रोपावर का दोहन करने और विश्वसनीय ऊर्जा समाधान देने के लिए उन्नत तकनीकों का उत्पादन करती है। वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की इक्विटी में एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी है। इस अवसर पर टीएचडीसीआईएल के कार्यपालक निदेशक टिहरी कॉम्प्लेक्स एल.पी. जोशी, टीएचडीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारी और जीई वर्नोवा, एचसीसी और विद्युत क्षेत्र के अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ परियोजना से जुड़े अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

# गायत्री जयंती महापर्व में लोगों ने लिया राष्ट्र और समाज के नव निर्माण का संकल्प

**हरिद्वार।** गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में चल रहे तीन दिवसीय गायत्री जयंती महापर्व के दूसरे दिन की शुरुआत चौबीस घंटे के अखण्ड जप के शुभारंभ के साथ हुई। इस विशेष अनुष्ठान में देश-विदेश से पधारे हजारों साधकों ने देश की अखण्डता एवं समृद्धि की प्रार्थना करते हुए भागीदारी की। गायत्री जयंती की पूर्व संध्या पर साधकों को संबोधित करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति युवा आइकॉन डॉ. चिन्मय पण्ड्या ने कहा कि यह समय जागने व जगाने का है। हमें ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के साथ देश की अखण्डता, समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाएँ और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के संवाहक बनें। इससे पूर्व सभा को संबोधित करते हुए महिला मण्डल की प्रमुख शैफाली पण्ड्या ने कहा कि माता भगवती देवी शर्मा की जन्मशताब्दी तथा सिद्ध अखण्ड दीपक का शताब्दी वर्ष 2026 को उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर देश-विदेश में ज्योति कलश यात्राओं के माध्यम से उनके विचारों और प्रकाश को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य हो रहा है।

# आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रही ग्रामोत्थान परियोजना

**हरिद्वार ( नवल टाइम्स )।** मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर जनपद के समस्त विकासखंडों में अल्ट्रा पूवर सपोर्ट, एंटरप्राइजेज (फॉर्म- नॉन फॉर्म), सीबीओ लेवल के एंटरप्राइजेज की स्थापना की गई है। इसी कड़ी में, विकासखंड खानपुर के न्यामतपुर गांव की एक साधारण महिला, सविता देवी, जिनका जीवन कभी गरीबी और अनिश्चितता से घिरा था, आज अपने समुदाय के लिए आशा की किरण बन गई हैं। उनके पति, संजय, खेतों में मजदूरी करते थे, और परिवार की आय इतनी कम थी कि अक्सर महीने के अंत में राशन खरीदने के पैसे भी नहीं बचते थे। सविता हमेशा अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखती थीं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था।

एक दिन, ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना और वीर सीएलएफद्वारा गांव में आयोजित एक बैठक ने सविता के जीवन को बदल दिया। सविता गंगा विहार समूह से जुड़ी हुई है, जो आस्था ग्राम संगठन और वीर सीएलएफसे जुड़ा हुआ है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस दौरान सविता को अल्ट्रा पूवर सपोर्ट के तहत 35 हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। सविता ने इस अनुदान के साथ-साथ स्वयं का भी 16,500 रुपये लगाये और परियोजना से जुड़कर अपनी आय सुधारने का संकल्प लिया।

अनुदान मिलने के बाद, सविता ने सुअर पालन का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया, उन्होंने 35 हजार रुपये में दो स्वस्थ सुअर-एक मादा और एक नर-खरीदे। बचे हुए पैसे से अपने आंगन में एक छोटा सा बाड़ा बनाया। शुरुआती संघर्षों के बावजूद, सविता की कड़ी मेहनत रंग लाई। चार महीने बाद, मादा सुअर ने आठ बच्चों को जन्म दिया। छह महीने बाद, इन बच्चों को बेचकर उन्हें 32 हजार रुपये की आय हुई।

इस आय से सविता ने अपने बच्चों की स्कूल फीस भरी, कुछ किताबें और यूनिफॉर्म खरीदे। उन्होंने घर में एक नया गैस चूल्हा भी लिया, धीरे-धीरे, उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार किया और उनकी आय बढ़ती गई। सविता की सफलता पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई और वे अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गईं। ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के सहयोग ने सविता को न केवल अपने परिवार का जीवन बदलने में मदद की, बल्कि उन्हें दूसरों को भी प्रेरित करने का अवसर मिला। आज, उनका परिवार एक बेहतर जीवन जी रहा है, और सविता की कहानी यह दर्शाती है कि कड़ी मेहनत, लगन और सही समर्थन से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है।

# पंजीकरण के लम्बित मामले एक माह के अन्दर कर दिये जायेंगे निस्तारित: प्रेस महापंजीयक

**देहरादून( नवल टाइम्स )।** भारत के प्रेस महापंजीयक योगेश कुमार बावेजा ने प्रकाशकों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पंजीकरण के लम्बित मामले 1 माह के अन्दर निस्तारित कर दिये जायेंगे और प्रेस सेवा पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों को तेजी से दूर करने का प्रयास किया जायेगा। शीर्ष पत्रकार संगठनों के पदाधिकारियों ने ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन के अध्यक्ष व पूर्व प्रेस काउंसिल सदस्य गुरिंदर सिंह के नेतृत्व में प्रेस महापंजीयक से मुलाकात कर समाचार पत्र प्रकाशकों के समक्ष आ रही दिक्कतों को तुरन्त हल किये जाने की जोरदार मांग की। ज्ञातव्य हो कि प्रेस सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन व अन्य कार्यों में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा था तथा इसमें प्रकाशकों को अनेक तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। मीटिंग में अति- प्रेस महापंजीयक डॉ. धीरज काकडिया, उप प्रेस पंजीयक आशुतोष मोहले व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

प्रतिनिधिमंडल में पूर्व प्रेस काउंसिल सदस्य अशोक नवरत्न, इंडियन एसोसियशन ऑफ प्रेस-एन-मीडियामेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सहयोगी, ऑल इंडिया स्मॉल न्यूजपेपर्स एसोसिएशन के दिल्ली प्रभारी अशोक कपूर, स्मॉल मीडियम बिग न्यूजपेपर्स सोसाइटी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार छाबड़ा, ठाकुर कृपाल सिंह, अशोक अनेजा देहरादून, आईएपीएम के उपाध्यक्ष अर्जुन जैन, सुशील वकील, ज्ञानेश्वर सिंह, सौरभ वाष्णेय, जे.के. मिश्रा, गौरव त्रिपाठी, व शुभम गुप्ता आदि सम्मलित थे। प्रेस महापंजीयक ने प्रकाशकों की विभिन्न समस्याएं सुनने के बाद कहा कि हम मानते हैं कि पिछले कुछ समय से प्रेस पंजीयन कार्यालय में काफी मामले लम्बित है जिन्हे एक माह के अन्दर निस्तारित करने का प्रयास जायेगा तथा प्रेस सेवा पोर्टल में जो तकनीकी दिक्कतों आ रही हैं उन्हे तत्काल दूर किया जायेगा। उन्होने प्रतिनिधिमंडल की मांग पर प्रदेशों की राजधानियों में स्थित पत्र सूचना कार्यालयों में प्रकाशकों को तकनीकी जानकारी देने के लिए सेमीनार/वेबनार आयोजित करने का भी आश्वासन दिया। उन्होने बताया कि हमारा उद्देश्य त्वरित गति से कार्यों को निपटाना है जो पूरी तरह फेसलैस हो, जिससे प्रकाशकों को पंजीकरण कार्यालय न आना पड़े। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सभी जिला प्राधिकरण द्वारा प्रेस सेवा पोर्टल पर लागिन/ऑनलाइन कार्य सुनिश्चत करने के लिए पीआरजीआई द्वारा पत्र लिखे जाने की मांग की, साथ ही समाचार पत्रों की नियमितता के लिए सिंगल विंडो बनाये जाने की भी मांग की, कि एक जगह समाचार पत्र की प्रति जमा कराने के बाद प्रकाशकों को अलग-अलग जगह समाचार पत्रों की प्रतियां न जमा करानी पड़ें। सभी प्रकाशक प्रतिनिधियों ने एक स्वर में यह भी मांग की कि प्रेस पंजीकरण के मामलों को निस्तारित किये जाने की प्रक्रिया में अनावश्यक आपत्तियां न लगाई जाए तथा प्रक्रिया का सरलीकरण कर प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

# मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में सचिवालय में किये गये तीन महत्वपूर्ण समझौते

- **उत्तराखण्ड में सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्य के लिए किया गया समझौता**
- **उत्तराखंड को डिजिटल टैलेंट केंद्र बनाने के लिए भी किया गया समझौता**
- **महाविद्यालयों में एआई आधारित व्यक्तित्व विकास के लिए आधुनिक कोर्स संचालन के लिए हुआ समझौता**

**देहरादून( नवल टाइम्स )।** मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में तीन महत्वपूर्ण समझौते किये गये। उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्य के लिए समझौता किया गया। उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का प्रमुख कौशल केंद्र बनाने की दिशा में सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और नैस्कॉम/आईटी-आईटीईएस सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य को उभरती टेक्नोलॉजी और छात्रों के रोजगार परक व्यक्तित्व विकास के लिए कौशल विकास केंद्र बनाने के लिए भी सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और वाधवानी फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड में सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए टाटा ट्रस्ट के साथ 10 साल के लिए किए गए समझौते के तहत जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा।

उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख कौशल केंद्र बनाने के लिए नैस्कॉम के साथ हुए समझौते के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में कोर्सेस को शैक्षणिक क्रेडिट के साथ शामिल किया जाएगा और प्रत्येक जिले में एक मॉडल कॉलेज को 'मेंटर संस्थान' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के लगभग 1.5 लाख छात्रों को फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, पायथन, जनरेटिव जैसे क्षेत्रों में जानकारी और कौशल विकास करना है।

उत्तराखंड को उभरती टेक्नोलॉजी और छात्रों के रोजगार परक व्यक्तित्व विकास के लिए कौशल विकास केंद्र बनाने हेतु वाधवानी फाउंडेशन के साथ तीन वर्षों के लिए किये गये समझौते के तहत राज्य के सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में कोर्सेस को अगले सत्र से शैक्षणिक क्रेडिट के साथ शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य के लगभग 1.20 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित व्यक्तित्व विकास और स्वरोजगार सम्बंधित कौशल विकास में सहायता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सामाजिक विकास, राज्य को डिजिटल टैलेंट का केन्द्र बनाने और एआई आधारित व्यक्तित्व विकास के आधुनिक कोर्स प्रारंभ करने के लिए आज हुए तीनों समझौते राज्य के लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरखण्ड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समाज के अंतिम छोर के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। राज्य के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र और वर्ग के लोगों को साथ लेकर अनेक नई पहल की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समझौते उत्तराखण्ड में आधुनिक कौशल से परिपूर्ण मानव संसाधन को तैयार करने और राज्य को आधुनिक एआई व साइबर सिक्योरिटी हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एआई अधारित पाठ्यक्रम उत्तराखंड को युवा छात्रों को रोजगार परक कौशल बढ़ाने और 21वीं सदी के लिए सॉफ्ट स्किल विकास की दिशा में कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में किये गये इन तीन महत्वपूर्ण समझौतों के लिए टाटा ट्रस्ट, नैस्कॉम और वाधवानी फाउन्डेशन का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सीईओ सेतु आयोग शत्रुघ्न सिंह, टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा, नैस्कॉम स्किल काउंसिल की सीईओ अभिलाषा गौड़, वाधवानी फाउन्डेशन के एक्जीक्यूटिव वीपी सुनील दहिया, उच्च शिक्षा सचिव रंजीत सिन्हा, सचिव राधिका झा, नितेश झा, चन्द्रेश यादव, वी षणमुगम, सी. रविशंकर उपस्थित थे।

# राज्यपाल ने होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक

**देहरादून।** राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को राजभवन में होटल एसोसिएशन, नैनीताल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान नैनीताल एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं, अवस्थापना विकास से जुड़ी समस्याओं और उनके संभावित समाधानों पर विस्तृत चर्चा की गई।

राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल का प्राकृतिक सौंदर्य और झील पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण हैं, और इनकी लोकप्रियता देश-विदेश तक फैली है। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता है और इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में आधुनिकता लाने और गुणवत्तापूर्ण पर्यटन (क्वालिटी टूरिज्म) को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में पार्किंग की समस्या पर राज्यपाल ने कहा कि छोटी-छोटी पार्किंग सुविधाएं, मल्टीस्टोरी पार्किंग और रोपवे जैसे विकल्पों के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मेट्रोपोल को अस्थायी रूप से राज्य सरकार को आवंटित किया गया है तथा रक्षा संपदा की भूमि को पार्किंग उपयोग हेतु प्रयास जारी हैं। इससे पार्किंग की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल की झील इस क्षेत्र की आत्मा है और इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाइड्रोग्राफर ऑफिस, देहरादून द्वारा झील का तकनीकी सर्वेक्षण किया गया है, जिससे झील की स्थिति का समुचित आकलन कर उसके संरक्षण हेतु वैज्ञानिक कदम उठाए जा सकेंगे। साथ ही उन्होंने पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी बल दिया।

बैठक के दौरान होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को कई सुझाव और समस्याओं से अवगत कराया। इनमें नैनीताल शहर की पार्किंग क्षमता बढ़ाने, ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने, रक्षा संपदा की भूमि को पार्किंग हेतु उपयोग में लाने, वैकल्पिक पेयजल स्रोतों की तलाश, सीवर प्रणाली का सुधार, पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार, कुमाऊंनी संस्कृति को स्थानीय व्यंजनों के माध्यम से बढ़ावा देने, रूरल आर्ट कमीशन की स्थापना तथा हॉर्टीकल्चर पर्यटन को प्रोत्साहन जैसे विषय प्रमुख थे। राज्यपाल ने सभी सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इन पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि इन विषयों को संबंधित विभागों, स्थानीय प्रशासन, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और जहां संभव हो, शीघ्र अमल किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ सुझावों पर कार्य पहले से ही प्रारंभ हो चुका है। इस अवसर पर होटल एसोसिएशन, नैनीताल के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट सहित होटल एसोसिएशन, नैनीताल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

# हेमकुंड साहिब यात्रा में तीर्थयात्रियों का उत्साह और रिकॉर्ड तोड़ दर्शन

**चमोली।** हेमकुंड साहिब, जो सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, में पिछले चार दिनों से रुक-रुक कर हो रही बर्फबारी के बावजूद तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है।

हिमालय की गोद में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र गुरुद्वारे में तीर्थयात्री अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ पहुंच रहे हैं। ठंडे मौसम और बर्फीली हवाओं के बीच भी, तीर्थयात्री पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हैं, जो उनकी गहरी आस्था और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। सरोवर का जल अत्यंत ठंडा होने के बावजूद, श्रद्धालु अपनी भक्ति के बल पर इस कठिन परिस्थिति में भी डटकर डुबकी लगा रहे हैं, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है।

पिछले आठ दिनों में श्री हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों की संख्या ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस दौरान 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे के दर्शन किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक रिकॉर्ड उपलब्धि है। यह आंकड़ा न केवल तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है, बल्कि श्री हेमकुंड साहिब के प्रति उनकी गहरी निष्ठा और आकर्षण को भी उजागर करता है। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करने वाली है, जो विश्व भर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है।

श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष, नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने चल रही यात्रा की प्रगति और इसके सुचारु संचालन पर चर्चा की। श्री बिंद्रा ने गोविंदघाट में एक स्थायी पुल के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसकी घोषणा पहले ही माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जा चुकी है। यह पुल यात्रा को और सुरक्षित व सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, विशेष रूप से बरसात और बर्फबारी के दौरान, जब अस्थायी मार्गों पर जोखिम बढ़ जाता है। इसके साथ ही, श्री बिंद्रा ने घांघरिया में तीर्थयात्रियों के लिए दो नए हॉल के निर्माण को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "यह हॉल तीर्थयात्रियों को ठहरने और विश्राम करने की बेहतर सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे उनकी यात्रा और अधिक आरामदायक होगी।

उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सक्रिय भूमिका और समर्पण के कारण ही यह यात्रा हर वर्ष सुगम और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो पाती है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, आवास, और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ), एटीएस एवं आईटीबीपी की विशेष टीमें भी शामिल हैं, जो यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ावों पर तैनात हैं।

श्री हेमकुंड साहिब यात्रा, जो मई से अक्टूबर तक चलती है, सिख धर्म के दसवें गुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तपोस्थली के रूप में जानी जाती है। यह स्थान न केवल सिख समुदाय के लिए, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है। पास में स्थित फूलों की घाटी और लक्ष्मण मंदिर भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र हैं। श्री बिंद्रा ने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की कि वे यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहें और प्लास्टिक-मुक्त यात्रा को बढ़ावा दें, जैसा कि राज्य सरकार ने भी संकल्प लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा की सफलता में श्रद्धालुओं का सहयोग और प्रशासन का समर्पण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।

# मुख्यमंत्री ने दी गंगा दशहरा की शुभकामनाएं

**देहरादून।** मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा दशहरा के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामना दी है। उन्होंने इस अवसर पर गंगा स्नान के लिये आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस पावन पर्व की बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवनदायिनी गंगा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। बिना गंगा व अन्य पावन नदियों के लोक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पावन नदियां हमारे अस्तित्व से जुड़ा विषय भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावन अवसर पर हमें गंगा एवं अन्य नदियों के साथ ही सभी जल स्रोतों को पवित्र रखने में भी अपना योगदान देना होगा।

**कानूनी सलाहकार**
**एड. अनुज कुमार शर्मा**
**चैम्बर नं. 20, रोशनाबाद**
**हरिद्वार (उत्तराखंड)**
**मो. 9837387718**

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजीव शर्मा ने किरण ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, निकट गुरूकुल कांगड़ी फार्मेसी, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखंड) से छपवाकर, म.नं. डी-31/2 आदर्शनगर कालोनी, गोल गुरूद्वारा, सेंटमेरी स्कूल के पीछे, ज्वालापुर हरिद्वार (उत्तराखंड) से प्रकाशित किया।

: सम्पादक :
संजीव शर्मा
मो. 8057605991/9897106991
ईमेल: navaltimes@gmail.com
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार होगा

**प्रबंध संपादक**
**डा. संदीप भारद्वाज**
**बिजनौर प्रभारी**
**विशाल शर्मा**

**सभी पद अवैतनिक हैं**